International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.11 No.2 November – December 2023

भारतीय शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती एकांकी 'नो एडमिशन'

डॉ. संतोष गायकवाड़

उपप्रचार्य एवं सहयोगी प्राध्यापक,

हिन्दी विभाग, सोनुभाऊ बसवंत महाविद्यालय,शहापुर,

मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई

Corresponding Author - डॉ. संतोष गायकवाड़

DOI - 10.5281/zenodo.17510629

शोध सारांश:

पिछले तीन दशकों में भारत में अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा का आकर्षण तेज़ी से बढ़ा है। अंग्रेज़ी को एक 'वैश्विक भाषा' माना जाता है और उच्च शिक्षा, व्यवसाय, सरकारी व निजी नौकरियों में सफलता की कुंजी अंग्रेज़ी का ज्ञान माना जाता है। यही मानसिकता अभिभावकों को अपने बच्चों का अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में दाखिला कराने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। निजी स्कूल इसी मानसिकता का फ़ायदा उठाते हैं और शिक्षा को प्रतिष्ठा का प्रतीक बना देते हैं। आज, किसी भी महानगर में, 'अंग्रेज़ी माध्यम' स्कूल का नाम प्रतिष्ठा, सुविधा और उच्च गुणवत्ता का प्रतीक बन गया है। इसलिए, हालाँकि इन स्कूलों में सीटें सीमित हैं, फिर भी हज़ारों आवेदन आते हैं - और यहीं से प्रवेश घोटाले शुरू होते हैं। 'नो एडमिशन' एकांकी इसी यथार्थ को उजागर करती है।

कुंजी शब्द : शिक्षा, बाजरीकरण, स्कूल, मध्यवर्गीय परिवार, शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, अभिभावक, आदि।

प्रस्तावना:

शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की आत्मा होती है। यह न केवल ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि व्यक्तिगत चरित्र, नैतिकता और सामाजिक चेतना का निर्माण भी करती है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यह न केवल ज्ञान और समझ बढ़ाती है, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार और भविष्य को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परंतु जब शिक्षा का उद्देश्य 'व्यवसाय' बन जाता है, तो उसकी आत्मा मर जाती है। भारत जैसे देश में, जहाँ 'सर्व शिक्षा अभियान' और 'शिक्षा का अधिकार' जैसे नियम लागू हैं, यह सोचकर भी दुःख होता है कि बच्चों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, गरीब या मध्यम वर्गीय अभिभावकों में आर्थिक तंगी है और पैसा शिक्षा पर हावी है। आज निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया इतनी जटिल और अपारदर्शी है कि गरीब या मध्यम वर्गीय अभिभावकों का बच्चा इसमें प्रवेश पाने का सपना भी नहीं देखता। शिक्षा, जिसे समानता का प्रतीक होना चाहिए, आज इसका

सबसे बड़ा उदाहरण बन गई है। आज के समय में, जब प्रतिस्पर्धा जीवन के हर क्षेत्र में फैल गई है, माता-पिता के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो उन्हें आत्मविश्वासी, सक्षम और आधुनिक बनाए। यही कारण है कि आज निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल इतने लोकप्रिय हो गए हैं।

आज देश में अराजकता का माहौल है। एक तरह से निजी अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा अब उच्च मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के अलावा किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। इस देश गरीब और मध्यवर्गीय परिवार के बच्चों की प्रतिभा का शोषण भी हो रहा है। इन सब परिस्थितियों के कारण शिक्षा का न केवल बाजारीकरण हो गया है, बल्कि यह एक अत्यधिक भ्रष्ट व्यवसाय भी बन गया है। किस तरह के छात्र इस तरह की शिक्षा ग्रहण करेंगे? और जब ये छात्र देश के विभिन्न क्षेत्रों का नेतृत्व करेंगे, तो देश का स्वरूप क्या होगा? यह एक बड़ा सवाल है। देश में भ्रष्टाचार और अनैतिकता बढ़ रही है, इन पर चिंता करने से कोई परिणाम नहीं निकलेगा। जब तक शिक्षा का बाजारीकरण नहीं रोका जाएगा, अन्य सभी नकारात्मक चीजें बढ़ती रहेंगी। देश की सभी समस्याओं की जड़ वर्तमान शिक्षा प्रणाली में है।

वर्तमान में, भारत में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। भारत सरकार ने अनिवार्य शिक्षा लागू की है। समय-समय पर, सरकार शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न बदलाव लाती रहती है, जिनमें अक्सर नीतियाँ और नियम शामिल होते हैं। हालाँकि, देश में शिक्षा केवल रोज़गार का साधन बनकर रह गई है। परिणामस्वरूप, चुनावों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। राजनीतिक दल शिक्षा और रोज़गार को लेकर कई चुनावी वादे करते हैं। स्पष्ट रूप से, उन्होंने शिक्षा के बढ़ते महत्व को पहचान लिया है। देश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था अब चरमरा रही है, शिक्षा की यह एक ऐसी स्थिति है जिसे सरकार खुद अक्सर नज़रअंदाज़ करती है। निजी संस्थानों पर सरकार का बढ़ता ज़ोर और महत्व जनता का सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर से भरोसा खत्म कर रहा है। बड़े नेताओं और अफसरों के बच्चे अक्सर निजी संस्थानों में पढ़ते हैं या विदेशों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत के कारण, अब इनकी पहुँच समाज के सबसे गरीब तबके तक ही सीमित रह गई है। गरीबों को भी अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

आज के दौर में शिक्षा न केवल राजनीति का बल्कि बाजारीकरण का भी शिकार हो गई है। देश के हर राज्य में शिक्षा के केंद्र बनाने के लिए बड़े-बड़े बाजार बनाए गए हैं, जिनमें दिल्ली का मुखर्जी नगर, राजस्थान का कोटा, महाराष्ट्र का पुणे और बिहार का पटना शामिल हैं। शिक्षा के इस बाजारीकरण को इस तरह समझा जा सकता है कि बिहार का लिट्टी चोखा और दिल्ली का मुखर्जी नगर अपनी सिविल सेवा प्रशिक्षण के लिए मशहूर है। हर तरह की शिक्षा के लिए अलग-अलग बाजार मौजूद हैं, जहां शिक्षा माफिया फल-फूल रहे हैं। गांवों में शिक्षा पाने के लिए अपनी जमीन बेचने वाला मजदूर वर्ग भी आज की चकाचौंध भरी शिक्षा को खरीदने

को मजबूर है। यह वादा शिक्षा के जरिए अच्छी नौकरियों की गारंटी है। देश का हर व्यक्ति अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी की तलाश में इसी बाजार का रुख करता है, जहां उसे पहले से तैयार माफिया घेर लेते हैं।

पिछले तीन दशकों में भारत में अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा का आकर्षण तेज़ी से बढ़ा है। अंग्रेज़ी को एक 'वैश्विक भाषा' माना जाता है और उच्च शिक्षा, व्यवसाय, सरकारी व निजी नौकरियों में सफलता की कुंजी अंग्रेज़ी का ज्ञान माना जाता है। यही मानसिकता अभिभावकों को अपने बच्चों का अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में दाखिला कराने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। निजी स्कूल इसी मानसिकता का फ़ायदा उठाते हैं और शिक्षा को प्रतिष्ठा का प्रतीक बना देते हैं। आज, किसी भी महानगर में, 'अंग्रेज़ी माध्यम' स्कूल का नाम प्रतिष्ठा, सुविधा और उच्च गुणवत्ता का प्रतीक बन गया है। इसलिए, हालाँकि इन स्कूलों में सीटें सीमित हैं, फिर भी हज़ारों आवेदन आते हैं - और यहीं से प्रवेश घोटाले शुरू होते हैं।

प्रवेश प्रक्रिया स्कूल की गुणवत्ता, पारदर्शिता और दूरदर्शिता को दर्शाती है। यह न केवल छात्रों को प्रवेश देने का एक माध्यम है, बल्कि उनकी शैक्षणिक योग्यता, बौद्धिक क्षमता और सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का आकलन करने का एक तरीका भी है। निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया केवल उन्हीं छात्रों के चयन के लिए डिज़ाइन की गई है जो स्कूल के मानकों के अनुसार प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा, कई स्कूल अभिभावकों के साथ साक्षात्कार भी आयोजित करते हैं। इस साक्षात्कार का उद्देश्य यह समझना है कि अभिभावक अपने बच्चे की शिक्षा के प्रति कितने सजग, संवेदनशील और सहयोगी हैं। हालाँकि अधिकांश स्कूल दावा करते हैं कि उनकी प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी है, कुछ मामलों में, रेफरल, डोनेशन और अनुचित प्रभाव की शिकायतें सुनने को मिलती हैं। इससे शिक्षा का बाजारीकरण बढ़ता है और योग्य छात्रों के अवसर प्रभावित होते हैं।

संजीव निगम द्वारा लिखित 'नो एडमिशन' एक यथार्थवादी एकांकी नाटक है। इस एकांकी में, संजीव निगम भारतीय शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलते हैं और शिक्षा के व्यवसायीकरण को उजागर करते हैं। प्रायवेट स्कूल दाखिले के नाम पर तरह-तरह की गड़बड़ियाँ कर रहे हैं और अभिभावकों के मन में दाखिले का डर पैदा करके पैसा कमा रहे हैं। दाखिले के नाम पर अभिभावकों को लूटा जा रहा है और पैसों के लिए दाखिला दिया जा रहा है। पूरी दाखिला प्रक्रिया अभिभावकों और बच्चों के लिए एक भयावह और त्रासद स्थिति पैदा कर रही है। आज शिक्षा व्यवस्था बाजार की ताकतों के हाथों में है और उन्होंने इसे सिर्फ़ पैसा कमाने का ज़रिया बना दिया है।

आज के प्रतिस्पर्धी युग में शिक्षा का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को सर्वोत्तम शिक्षा मिले और उनका भविष्य उज्ज्वल हो। इसलिए, ज़्यादातर माता-पिता अपने बच्चों का दाखिला निजी अंग्रेज़ी माध्यम वाले स्कूलों में कराने की कोशिश करते हैं। माना जाता है

कि ये स्कूल अपेक्षाकृत उच्च शैक्षणिक स्तर, सुविधाएँ, अनुशासन और भाषाई वातावरण प्रदान करते हैं। हालाँकि, इन स्कूलों में दाखिला पाना एक कठिन और जटिल प्रक्रिया बन गई है। 'नो एडमिशन' एकांकी के रेखा और विनीत अपने बेटे सोनू का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाना चाहते हैं। इसके लिए विनीत रात से ही लाईन में लग जाता है। यहां बड़े अधिकारी, डॉक्टर, व्यापारी और यहां तक कि पुलिस अधिकारी भी रात में अपने बच्चों के एडमिशन फॉर्म लेने के लिए अपने वफादार नौकर को स्कूल के सामने भेज देते थे और सुबह चार बजे से ही अपने नौकर को हटाकर खुद लाइन में खड़े हो जाते थे। विनीत जब रात में एडमिशन फॉर्म लेने रात को ही लाइन में लग जाता है तो देखता है कि, "बड़े-बड़े अफसरों, डॉक्टरों, व्यापारियों यहाँ तक के पुलिस के अधिकारियों ने भी अपने बच्चों के लिए एड्मिशन का फॉर्म लेने के लिए अपने गुर्गों को रात को ही स्कूल के आगे लिटा दिया था और सुबह चार बजे से ही वे सब लोग अपने गुर्गों को हटाकर खुद लाइन में लग गये थे।"[१] बड़े प्राइवेट विद्यालय की फीस आम आदमी के हौसले पस्त कर देती है । हर गतिविधि के लिए अभिभावकों को फीस देनी पड़ती है। रेखा जब उस स्कूल की फीस के बारे में पूछती है तो विनीत कहता है-"हाँ, फीस तो इतनी है रेखा, पर...उसके साथ स्पोर्ट्स फीस हजार रुपये, लाइब्रेरी फीस हजार रुपये, कल्चरल फीस सात सौ रुपये, हॉर्स राइडिंग फीस आठ सौ रुपये, और स्कूल फ़ंड में पाँच सौ रुपये देने होंगे।"[२]

काफी प्रयास के बाद जब उन्हें प्रवेश पत्र मिलता है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई बड़ी लड़ाई जीत ली हो। काफी प्रयास और कड़ी मेहनत के बाद जब उन्हें सुबह प्रवेश पत्र मिलता है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई बड़ी लड़ाई जीत ली हो। घर जाते समय वे आवेदन पत्र के साथ सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान की दो किताबें भी ले जाते हैं ताकि दंपति स्कूल में साक्षात्कार की अच्छी तैयारी कर सकें। अपने बेटे के प्रवेश साक्षात्कार के दिन, वे दोनों अच्छी तरह से तैयार होकर स्कूल जाते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य उनसे तरह-तरह के सवाल पूछते हैं। प्राइवेट विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए अभिभावकों का शिक्षित होना भी जरूरी है। जब प्रिन्सिपल रेखा और विनीत को यह पूछती है कि आप दोनों पढ़े-लिखे तो हो न। इसपर जब रेखा कहती है कि यह सवाल आपने क्यों पूछा? तब प्रिन्सिपल जो जबाब देती है, उससे शिक्षा व्यवस्था में फैली अनास्था और उदासीनता ही उजागर होती है। वह कहती है-"अरे भई सीधी-सी बात है अगर पेरेंट्स पढ़े-लिखे नहीं हुए तो बच्चों को पढ़ायेगा कौन?...हमें तो एनुअल दे, स्पोर्ट्स डे, टीचर्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे, ग्रीन डे....वगैरह मनाने से फुरसत ही कहाँ मिलती है? इसलिए बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा माँ-बाप को ही उठाना होता है..."[३] प्रधानाचार्य इस बात पर जोर देती हैं कि उनके पास एक कार होनी चाहिए। अगर वे एक कार खरीदते हैं और उसके दस्तावेज स्कूल में पेश करते हैं तभी उनके बच्चे को प्रवेश मिलेगा। अभिभावकों के पास गाड़ी होनी चाहिए क्योंकि यह स्कूल के स्टेटस को

दर्शाता है-"आपको तो गाड़ी इसलिए लेनी है क्योंकि यह हमारे स्कूल की इज्जत का सवाल है। सब लोग हमारे स्कूल के बारे में यही कहते हैं यहाँ तो सिर्फ मोटारकार वालों के बच्चे पढ़ते हैं ...आप भी फौरन कार खरीद कर उसके कागजात की फोटोकॉपी स्कूल में जमा करवा दीजिएगा उसी के बाद आपके बच्चे का एडमिशन पक्का होगा।"[४] जाहिर है, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के अभिभावकों को न केवल ट्यूशन फीस या स्कूल की अन्य फीस देकर राहत मिलती है, बल्कि उन्हें स्कूल के स्टेटस का दबाव भी झेलना पड़ता है।

प्रिन्सिपल रेखा और विनीत से एक कविता सुनाने को कहती हैं। जब वे हिंदी कविता सुनाते हैं तो वह गुस्सा हो जाती हैं और उन्हें डांटती हैं, और आदेश देती हैं कि वे अगले कमरे में जाकर एक अंग्रेजी कविता याद करें और उसे सुनाएँ। तभी लाला बनारसी दास आ पहुँचते हैं। लाला बिना अनुमति के प्रिंसिपल के केबिन में घुस जाते हैं और तुरंत उन्हें अपनी फैक्ट्रियों, सुपरमार्केट, बंगलों और कारों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में प्रिंसिपल को लाला का व्यवहार अजीब और विचित्र लगता है, लेकिन जैसे ही वह उससे दाखिले के बदले पांच लाख रुपये का चेक देने की बात करता है, उसका रवैया पूरी तरह बदल जाता है- "क्या? पाँच लाख का डोनेशन?...अरे तो सेथजी ये पॉइंट आपको सबसे पहले बताना चाहिए था...खामख्वाह आपको इतनी देर परहसन होना पड़ा...आप बैठिए न प्लीज...बैठिए..."[५] प्रिंसिपल उसे विश्वास दिलाती है कि उसके पोते लल्लू को स्कूल की एकमात्र खाली सीट पर दाखिला मिल जाएगा। वह लाला से कोई सवाल नहीं पूछती और न ही उसका इंटरव्यू लेती है। प्रिंसिपल, जो दूसरे अभिभावकों से सीधे बात नहीं कर सकती, लाला से मुस्कुराते हुए बात करने लगती है। इस तरह, लाला प्रिंसिपल को पैसे देकर अपने पोते लल्लू का दाखिला करवा देता है, जबकि रेखा और विनीत को, जिन्हें अभी भी उम्मीद थी, एडमिशन के लिए मना कर देती है और अगले साल फिर आने के लिए कहती है। बेचारी रेखा और विनीत यह अन्याय देखते रह जाते हैं। इस प्रकार, मध्यम वर्गीय माता-पिता आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को दाखिला देने से वंचित रह जाते हैं, जबकि लाला बनारसीदास जैसे अमीर लोग आसानी से दौड़ जीत जाते हैं। रेखा और विनीत बहुत मायूस, जैसे उनके सपने टूट गये हो, वापस लौटते हैं-"परंतु यहीं से हमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था का वह चेहरा दिखाई पड़ता है जिसमें आज अनेक स्कूल संलिप्त हैं, और अनेक माँ-बाप उनके शोषण का शिकार हो रहे हैं । शिक्षा व्यवसाय का रूप लिए हुए है।"[६]

निष्कर्ष:

इस प्रकार 'नो एडमिशन' एकांकी बताती है कि किस प्रकार आज शिक्षा व्यवस्था बाजार केन्द्रित हो चुकी है। आम आदमी और उसकी मजबूरियाँ शिक्षा व्यवस्था के लिए कोई मायने नहीं रखतीं। सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर ऐसे विद्यालयों के लिए नियम बनाए जाते हैं ताकि प्रवेश प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे।

अभिभावकों को भी जागरूक रहना चाहिए कि वे किसी प्रकार की अनुचित प्रक्रिया का हिस्सा न बनें। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। यदि निजी विद्यालय अपनी प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी, समान और छात्र-केंद्रित बनाएँ, तो वे समाज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। अभिभावकों का भी यह दायित्व है कि वे विद्यालय चुनते समय केवल नाम या दिखावे पर नहीं, बल्कि उसकी शिक्षण पद्धति, नैतिक मूल्यों और वातावरण पर ध्यान दें।

संदर्भ सूची:

१. सं. डॉ. सिंह अनिल, एकांकी-सुमन, नो एडमिशन, संजीव निगम, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण: २०२१, पृ. १२८

२. वही, पृ. १२९

३. वही, पृ. १३१

४. वही, पृ. १३१

५. वही, पृ. १३५

६. सं. डॉ. सिंह अनिल, एकांकी-सुमन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण: २०२१, पृ. १४४